(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एम वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ आई आरडीपी की उपेक्षा, इसे कार्यान्वित करने/भाग न लेने, आईआरडीपी की उपलब्धि की धीमी प्रगति आदि जैसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दिया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों से कहा है कि वे उनके लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें और आईआरडीपी के अंतर्गत पर्याप्त और समय पर ऋण भी प्रदान करें । यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अधिक ऋण उपलब्ध कराए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को विस्तृत हिदायतें जारी की हैं । सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में जब कभी अनियमितताएं शिकायतें प्राप्त होती हैं तब भारतीय रिजर्व बैंक उनकी जांच करता है और बैंकों को उपयुक्त परामर्श देता है ।

Loans to SSIs by Public Sector Banks in Gujarat

4352. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: (a) the number of loan applications received from Small Scale Industries by the Public Sector Banks in Gujarat during the last three years and the amounts sanctioned therefor;

(b) whether the above banks have provided loans to the small scale industries in time to avoid sickness in the industry;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the action proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) The data reporting system of the Reserve Bank of India (RBI) does not generate information in the manner asked for. However, according to the latest available data furnished by RBI, loans disbursed by scheduled commercial banks to small scale industrial (SSI) units in the State of Gujarat as at the end of June 1991, June 1992 and June 1993 were as under:

(Rs. crores)

Year ending	No. of Account	Amount disbursed
June, 1991	36466	248.15
June, 1992	39697	241.34
June, 1993	15230	233.16

(b) to (d) RBI has issued instructions to all scheduled commercial banks that applications upto a credit limit of Rs. 25,000|- should be disposed of within a fortnight and those for over Rs. 25.000|- with in 3-4 weeks from the date of receipt of applications. Banks have also been advised that requests for increase in credit limits should be considered expeditiously and decision taken promptly and in any case within six weeks.